

ट्रंप के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर

2700 शहरों और कस्बों में राष्ट्रव्यापी नो किंग्स हुए विरोध प्रदर्शन

न्यूयॉर्क/सेन फ्रांसिस्को, 19 अक्टूबर. अमेरिका में शनिवार को 2,700 शहरों और कस्बों में लाखों लोग राष्ट्रव्यापी नो किंग्स विरोध प्रदर्शनों में सड़कों पर उतर आये. यह अमेरिकी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एकदिवसीय विरोध प्रदर्शन था.

उल्लेखनीय है कि नो किंग्स आंदोलन का यह दूसरा प्रदर्शन था. इससे पहले इसी साल 14 जून को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्म



दिन पर पहले प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसमें पचासों राज्यों से हजारों लोगों ने भाग

लिया था. प्रदर्शनकारी ट्रंप के तानाशाही रवैये के खिलाफ सड़कों पर उतर आए. उनका

कहना है कि ट्रंप एक लोकतंत्र में राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो असंवैधानिक है.

न्यूयॉर्क शहर में 1,00,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी टाइम्स स्क्वायर पर जमा हुए थे, जिनके हाथों में नफरत अमेरिका को महान नहीं बनाएगी, अमेरिकी आज़जन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीडी) को न्यूयॉर्क शहर से बाहर करो, हमारे संविधान की रक्षा करो, लोकतंत्र, राजतंत्र नहीं और संविधान वैकल्पिक नहीं है जैसे पोस्टर थे. एक प्रदर्शनकारी टोनी चाली ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास एक परंपरा है और प्रवासी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.

अमेरिका ने टाइम सिस्टम को किया टारगेट

► नेशनल सिक्वोरिटी एजेंसी पर साइबर अटैक का आरोप

बीजिंग, 19 अक्टूबर. चीन ने रविवार को एक बड़ा खुलासा करते हुए अमेरिका की नेशनल सिक्वोरिटी एजेंसी पर साइबर अटैक का आरोप लगाया है.

चीन की स्टेट सिक्वोरिटी मिनिस्ट्री के मुताबिक, अमेरिका ने 2022 से लेकर 2024 तक चीन के नेशनल टाइम सर्विस सेंटर को बार-बार निशाना बनाया. एक वीचैट पोस्ट में दावा किया कि ने सेंटर के कर्मचारियों के डिवाइसेज से संवेदनशील डेटा चुराने के लिए एक विदेशी मोबाइल ब्रांड का मैसेजिंग सर्विस को कमजोरी का इस्तेमाल किया. हालांकि, उस ब्रांड का नाम उजागर नहीं किया गया.



चीन के अनुसार, ये साइबर हमले केवल डेटा चोरी तक सीमित नहीं थे. 2023-24 के बीच ह्म ने 42 तरह के स्पेशल साइबर अटैक टूलस का इस्तेमाल कर सेंटर के इंटरनल नेटवर्क सिस्टम्स को भेदने की कोशिश की. इसका मकसद चीन को टाइम सर्विस और उससे जुड़ी रणनीतिक सेवाओं जैसे कम्यूनिकेशन, फाइनेंस, एनर्जी और डिफेंस को अस्थिर करना था. मिनिस्ट्री ने दावा किया कि चीन के पास इन हमलों के पुख्ता तकनीकी प्रमाण हैं.

आरोप है कि अमेरिका उन साइबर गतिविधियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है जो वह खुद करता है. चीन ने वेस्टर्न गवर्नमेंट्स द्वारा लगाए गए चीनी हैकर्स पर आरोपों को भी दोहरे मापदंड बताया. चीन का यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ताइवान और जियोपॉलिटिक्स को लेकर संबंध बेहद संवेदनशील स्थिति में हैं. हालांकि, इस मामले पर अभी तक अमेरिकी एग्जेंसी या ह्म की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. जैसे-जैसे तकनीकी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है.

मिलान से दिल्ली नहीं आ सकी फ्लाइट, अब नई उड़ान तैयार

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर. एयर इंडिया ने इटली के मिलान में फंसे 256 भारतीय यात्रियों को दिल्ली लाने के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की है.

दरअसल, 17 अक्टूबर को मिलान से दिल्ली आने वाली उड़ान संख्या 38 को तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दिया गया था, जिससे यात्रियों को दिवाली से पहले भारत लौटने में परेशानी हुई. कंपनी ने इस स्थिति पर खेद जताते हुए कहा कि सभी यात्रियों के लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई थी. हालांकि एयर इंडिया ने यह भी स्वीकार किया कि संसाधनों की सीमा के कारण कुछ यात्रियों को एयरपोर्ट से दूर होटल में ठहराया गया. 17 अक्टूबर की

रद्द उड़ान में 256 यात्री और 10 चालक दल के सदस्य सवार होने वाले थे. यात्रियों की बढ़ती चिंता को देखते हुए एयर इंडिया ने 19 अक्टूबर को एक विशेष उड़ान संचालित करने का निर्णय लिया है. यह विमान मिलान से उड़ान भरेगा और 20 अक्टूबर की सुबह दिल्ली पहुंचेगा. एयर इंडिया ने एक आधिकारिक बयान में कहा है हम अपने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोपरि मानते हैं. कठिन परिस्थितियों में भी हम उन्हें रह संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. एयर इंडिया का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब दिवाली के त्योहार के कारण अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है.

सरकार हरसंभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध

गृहमंत्री अमित शाह ने 1950 करोड़ की सहायता मंजूर की

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर. भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों को मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है.

गृह मंत्रालय ने रविवार को जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 के लिए राज्य आपदा राहत कोष के अंतर्गत कर्नाटक और महाराष्ट्र को 1,950.80 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त के रूप में अग्रिम सहायता जारी की गई है. दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित कर्नाटक और महाराष्ट्र को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों

इस साल अब तक के तहत 27 राज्यों को 13,603.20 करोड़ रुपये, जबकि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत 15 राज्यों को 2,189.28 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है. इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 21 राज्यों को 4,571.30 करोड़ और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से 9 राज्यों को 372.09 करोड़ रुपये भी जारी किए हैं. गृह मंत्रालय ने बताया कि राहत एवं बचाव कार्यों के लिए इस वर्ष देशभर में एनडीआरएफ की रिक्तों 199 टीमें तैनात की गईं. सेना और वायुसेना को भी जरूरत के अनुसार बुलाया गया, ताकि बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित लोगों को समय पर सहायता मिल सके. इस कदम से जहां प्रभावित राज्यों को राहत मिलेगी.



राज्यों के लिए 1,950.80 करोड़ रुपये की अग्रिम सहायता जारी करने की मंजूरी दी है. इसमें से कर्नाटक को 384.40 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 1,566.40 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है. इन राज्यों में मानसून के दौरान

अत्यधिक वर्षा और बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई थी, जिससे जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में राज्यों को हरसंभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है.

एक नजर में



दक्षिण अरब सागर में चक्रवाती तूफान की आशंका चेन्नई, 19 अक्टूबर. तमिलनाडु में मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि दक्षिण अरब सागर में बने निम्न दबाव क्षेत्र के अगले कुछ दिनों में चक्रवाती तूफान में बदलने से राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है. इस चक्रवात तूफान की संभावना के मद्देनजर भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने समुद्र में एक जहाज तैनात किया है. इसे समुद्री क्षेत्र में गश्त लगाने का काम सौंपा गया है. रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, चक्रवात अलर्ट. दक्षिण-पूर्व अरब सागर में निम्न दबाव क्षेत्र के चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है. इसमें आगे कहा गया, भारतीय तटरक्षक बल का जहाज अभिराज तटीय जल में गश्त कर रहा है और उसने नाविकों और समुद्र में मौजूद मछुआरों को मौसम की चेतावनी दी है और मछुआरों से बंदरगाह पर लौटने का आग्रह किया.

पाकिस्तान में बाढ़ से हुआ नुकसान

इस्लामाबाद, 19 अक्टूबर. पाकिस्तान में हाल में आयी बाढ़ के कारण लगभग 2.9 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है. पाकिस्तान के योजना, विकास और विशेष पहल मंत्री अहसान इकबाल ने बाढ़ से हुये नुकसान की प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट जारी करते हुये कहा कि इस बाढ़ के कारण देश में व्यापक नुकसान हुआ है. इससे हुये नुकसान का पता लगाने के लिए विस्तृत आकलन किया जा रहा है. श्री इकबाल ने कहा कि अभी लगभग 822 अरब रुपये नुकसान का अनुमान है. इसमें कृषि क्षेत्र में लगभग 430 अरब रुपये और बुनियादी ढाँचे में 307 अरब रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने बताया कि बाढ़ से देश भर में लगभग 2,29,000 घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार, कुल नुकसान से जुलाई 2025 से जून 2026 तक पाकिस्तान की जीडीपी वृद्धि दर में 0.3 से 0.7 प्रतिशत अंकों की कमी आने की उम्मीद है.

ईरान ने प्रतिबंधों को अमान्य घोषित किया

तेहरान, 19 अक्टूबर. ईरान ने शनिवार को कहा कि वह अब 2015 के संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) के प्रतिबंधों से बंधा नहीं है. यह समझौता समाप्त हो चुका है, लेकिन उसने कूटनीतिक प्रति प्रतिबद्धता दोहराई. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा प्रस्तावित जेसीपीओए पर जुलाई 2015 में विधान में ईरान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए थे.

सेनाएं अब आतंकवाद पर वार को तैयार

भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त अभ्यास से जोश

ऑस्ट्रेलिया 19 अक्टूबर. आतंकवाद, उग्रवाद और प्राकृतिक आपदाओं जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं एकजुट हो चुकी हैं.

ऑस्ट्रेलिया की धरती पर चल रहा 'ऑस्ट्राहिंद-2025' अभ्यास न सिर्फ सामरिक दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को भी नई मजबूती दे रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच चल रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास 'ऑस्ट्राहिंद-2025' इन दिनों पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ जारी है.



आतंकवाद-रोधी अभियानों, उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में संचालन और आपदा राहत अभियानों पर केंद्रित यह अभ्यास दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभ्यास का यह चौथा संस्करण है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी. 'ऑस्ट्राहिंद' अब एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा मंच बन चुका है.

इजरायल को गाजा से दो बंधकों के शव मिले

यरूशलम, 19 अक्टूबर. इजरायल को गाजा से दो शव मिले हैं, जिनके बारे में हम्मास का कहना है कि वे बंधक हैं.

यह जानकारी इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार रेडक्रॉस के माध्यम से इजरायली बलों को सौंपे गए थे शव इजरायल लाए गये हैं और उनकी औपचारिक पहचान की जाएगी. हम्मास ने पहले कहा था कि शनिवार को फिलिस्तीनी क्षेत्र में शव बरामद किए गए थे. गौरतलब है कि शनिवार से पहले 28 मृत बंधकों में से 10 के अवशेष इजरायल को लौटा दिए गए थे. इस देरी से इजरायल में

आक्रोश फैल गया है, क्योंकि पिछले हफ्ते हुए युद्धविराम समझौते की शर्तों के तहत गाजा से सभी जीवित और मृत बंधकों की रिहाई की बात कही गई थी. हम्मास का कहना है कि उसे मलबे के नीचे बचे हुए शवों को खोजने में काफी मशक़त करनी पड़ रही है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने गाजा और मिश्र के बीच राफा सीमा को आपत्ती सूचना तक बंद रखने का आदेश दिया है और कहा है कि अंतिम बंधक अवशेषों की वापसी और युद्धविराम समझौते के कार्यान्वयन के आधार पर इसे फिर से खोलने पर विचार करेंगे. राफा क्रॉसिंग उन फिलिस्तीनियों के लिए महत्वपूर्ण है.

संसद के पास आग से खुली सुरक्षा की पोल

► अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की व्यवस्था को दया योग्य बताया

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर. राजधानी दिल्ली में संसद से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित 'ब्रह्मपुत्र भवन' में लगी आग ने न केवल सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी, बल्कि सरकारी लापरवाही की हद भी दिखा दी. सांसद साकेत गोखले ने इस लापरवाही पर कड़ा हमला करते हुए सोशल मीडिया पर विस्तृत पोस्ट साझा की, जिसे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट करते हुए दिल्ली की व्यवस्था को दया योग्य बताया. दमकल की देरी, जलहीन फायर सिस्टम और बिना

प्रतिदिन एक फीसदी के रिक्त के झांसे में छह करोड़ की टगी

जशपुर, 19 अक्टूबर. छत्तीसगढ़ के जशपुर पुलिस ने शेरार बाजार और कृषि व्यवसाय के नाम पर चलाए गए एक बड़े निवेश घोटाले का पर्दाफाश किया है.

अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की टगी का खुलासा हुआ है. इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपियों ने सी बुल्स ग्लोबल सॉल्यूशन नामक एक फर्जी कंपनी बनाकर निवेशकों को प्रतिदिन एक प्रतिशत ब्याज का लालच लंबे समय तक दिया था. इस टगी के शिकार जशपुर, कोरवा, जांजगीर-चांपा, अंबिकापुर, बिलासपुर और

शक्ति जिलों के निवासी बने. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य रूप से टगी के शिकार हुए लोगों में जगेश्वर लाल यादव (1.80 करोड़), लक्ष्मण केशवानी (95 लाख), भूषण पटेल (33 लाख), डॉक्टर पीताम्बर साय निराला (25 लाख), राजेश देवांगन (15 लाख) और कमलेश यादव (10 लाख) शामिल हैं.

एसडीओपी पथलगांव धुर्वेश जायसवाल के नेतृत्व में चल रही जांच से पता चला है कि आरोपियों हरिशरण देवांगन (जिला शक्ति) और संतोष कुमार साहू (जांजगीर-चांपा) ने कई जिलों में बैठकें आयोजित करके लोगों को फंसाया.

आज का इतिहास

- 1568 मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया।
- 1740 मारिया थेरेसा ऑस्ट्रिया, बोहेमिया के शासक बने।
- 1774 कोलकाता भारत की राजधानी बना।
- 1880 एफस्टैडम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।
- 1904 बोलीविया ने शांति व मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया।
- 1905 रूस में 11 दिन तक चली हड़ताल की शुरुआत हुई।
- 1921 फ्रांस और तुर्की के बीच अंकारा संधि पर हस्ताक्षर किए गए।
- 1946 विधाननाम की डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सरकार ने इस दिन को महिला दिवस के रूप में घोषित किया।

घोटालों में शामिल लोगों को हथकड़ी लगाकर वापस भेजा

सोल. आंनलाइन घोटालों में कथित संलिप्तता को लेकर कंबोडिया में हिरासत में लिए गए दक्षिण कोरिया के 59 नागरिकों के को हथकड़ी लगाकर स्वदेश भेज दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार यह समूह शनिवार सुबह इंचियन हवाई अड्डे पर पहुंचा, इससे कई दिन पहले दक्षिण कोरिया ने अपने नागरिकों के हिरासत में लिये जाने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक टीम कंबोडिया भेजी थी. रिपोर्ट के अनुसार द. कोरिया वापस भेज गये लोग उन लगभग 200,000 लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि वे दक्षिण पूर्व एशिया में धोखाधड़ी की योजनाओं में फंस गए हैं.

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर. भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा चुनाव और देश के आठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में हो रहे उपचुनावों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है. आयोग का कहना है कि इन नियुक्तियों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है, ताकि सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को समान अवसर मिल सके. संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आयोग ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की

तैनाती की है. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 121 सामान्य पर्यवेक्षक और 18 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जबकि दूसरे चरण में 122 सामान्य और 20 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं. इसके अलावा, आठ विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनावों के लिए आठ सामान्य और आठ पुलिस पर्यवेक्षक भेजे गए हैं. सभी पर्यवेक्षकों ने अपने-अपने क्षेत्रों का पहला दौरा पूरा कर लिया है और अब वे संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थायी रूप से तैनात हैं. चुनाव आयोग ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे पूरी चुनावी प्रक्रिया पर बारीकी से निगरानी रखें और यह सुनिश्चित करें.

मामला उजागर 676 फीसदी फेकल्टी का खुलासा, 22 कॉलेजों में था एक ही शिक्षक

अन्ना यूनिवर्सिटी में घोटाला, रजिस्ट्रार-डायरेक्टर को हटाया

चेन्नई, 19 अक्टूबर. तमिलनाडु के प्रमुख तकनीकी शिक्षा संस्थान अन्ना विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों में घोस्ट फेकल्टी का मामला सामने आया है.



परिणामस्वरूप विश्व विद्यालय के सिंडिकेट ने रजिस्ट्रार, संबद्धता निदेशक और अन्य अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है. यह कार्रवाई उनके खिलाफ सतर्कता (विजिलेंस) मामले के बाद की गई है. पिछले साल अगस्त में विश्वविद्यालय की विस्तृत जांच ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसमें पता चला कि 676

20 अन्य 10 संस्थानों की पेरौल पर थे. सभी घोस्ट फेकल्टी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है.

भ्रष्टाचार विरोधी एनजीओ अरप्पोर इयक्म ने जुलाई में यह घोटाला उजागर किया था, जिसमें बताया गया कि 2023-24 में 353 शिक्षक कई इंजीनियरिंग कॉलेजों में काम कर रहे थे और कार्रवाई की मांग की गई थी. तकनीकी शिक्षा निदेशालय के आयुक्त टी. अब्राहम की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पैनल ने पाया कि संबद्ध कॉलेजों ने 2023-24 में लगभग 2000 संकाय पदों को फर्जी नियुक्तियों के साथ भरा था.

हालांकि 200 से अधिक कॉलेज इस रिकॉर्ड में शामिल पाए गए, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीपीसी) ने केवल उप-कुलपति आर. वेलारज, रजिस्ट्रार जे. प्रकाश, संबद्धता निदेशक वी.आर. गिरी देव और आठ अन्य लोगों के खिलाफ घोस्ट फेकल्टी घोटाले के संबंध में मामला दर्ज किया है. जबकि राज्य सरकार ने श्री वेलारज को उनके सेवानिवृत्ति के दिन यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर के रूप में सेवा समाप्त होने पर निलंबित कर दिया था. लेकिन राज्यपाल आर.एन. रवि जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, ने इसे रद्द कर दिया और उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया. शनिवार को विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने जो राज्यपाल द्वारा श्री वेलारज के निलंबन को रद्द करने और अभियोजन की अनुमति देने के बाद आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था. डीवीपीसी द्वारा नामित सभी अधिकारियों को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का निर्णय लिया. विश्वविद्यालय के सूत्रों ने कहा, सिंडिकेट ने डीवीपीसी द्वारा मामले में नामित सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का फैसला किया है.